हिन्दुस्तान

संगोष्ठी आयोजित

पटना (सं.सू.)। वाणी एवं आभा, नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति विषय पर शनिवार को एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी की अध्यक्षता उपवन के कार्यकारी निदेशक व्यास जी ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड सिर्फ एनजीओ ही नहीं बल्कि उक्त संस्था को राशि मुहैया कराने वाले अधिकारी को भी दंड़ित किया जाना चाहिए। उन्होंने केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस मौके पर आद्री के निदेशक व अर्थशास्त्री सी.पी. घोष ने कहा कि मनुष्य के लिए सारे काम व्यक्तिगत नहीं होते बल्कि उनमें सामाजिकता भी होली है। इसी के तहत लोक जनोपयोगी कार्य करते हैं। किसी भी मनुष्य या संगठन के यदि सामाजिक सरोकार गीरि हो तभी समाज में उसकी खास पहचान बनती है। सामाजिक कार्यकर्ता अवनीष ने कहा कि सरकार अब अपनी नीतियों में स्वैच्छिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं को भी शामिल करने लगी है। पहले नीतियां बंद कमरे में बनाई जाती थी। उन्होंने कहा कि यह नीति पहली बार राष्ट्रीय हित में बात करती है। 1971-72 से ही इस क्षेत्र में नीति बनाने की बात होने लगी थी जो अब जाकर लागू हुई है। पहली बार सरकार ने स्वैच्छिक संगठनों पर जिम्मेदारी दी है।

Hindustan Times

NGOs demand a say in policy-making

HT Correspondent
Patna, December 1

VARIOUS NGOs on Saturday demanded direct participation in the state-level committee constituted to formulate the 'state policy on voluntary organisations' on the basis of 'National Policy on Voluntary Sector-2007'.

Ganesh Prasad, Director of Adithi, while addressing a workshop on "State Consultations on National Policy on Voluntary Sector," organised by Voluntary Action Network India (VANI), said the State Government must allow voluntary organisations to be a part of the policy making body.

"Network of voluntary organisations should strengthen themselves and form a committee to provide proper help and guidance to the committee framing the policy," he said, demanding that there should a transparency in draft reports of voluntary organisations' policies at the government level. He also advocated holding a public opinion poll regarding the policy.

Dr C S Vaiyas, Executive Director of UPVAN, criticised the National Policy of Voluntary Organisations. "It is more than seven months when the policy was framed but no team has so far been formed to accredit various NGOs as the policy talks about performance-based accreditation of voluntary organisations," he said.

Dr P P Ghosh, Director of Asian Development Research Institute, said the NGOs worked for those collective activities where the government or market did not have any reach.

He said the National Policy has not made it clear which organisation should be called a voluntary organisation. "As per the policy's norm a terrorist organisation may also call itself a voluntary organisation", he added. Pranav Kumar of VANI proposed a vote of thanks.

राष्ट्रीय
सहारा

अस्पष्ट है स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी राष्ट्रीय नीति

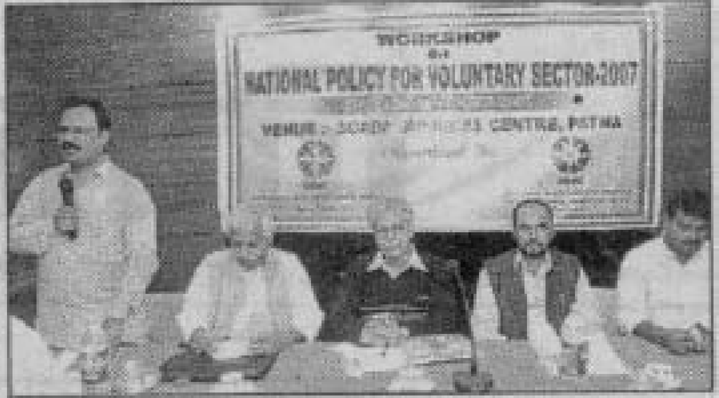

उपवन यू. पी. के कार्यकारी निदेशक डॉ. सी. एस. व्यास ने कहा कि सरकार की स्वैच्छिक क्षेत्रक संबंधी राष्ट्रीय नीति-2007 एक स्वागत योग्य कदम है, लेकिन इस नीति में कई कमजोरियां भी है। यह नीति किन लोगों के बारे में है। किन संस्थाओं के बारे में है। राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर क्या तथा कैसे करना चाहती है ? इसमें इसका भी साफ रास्ता नहीं दिख रहा है। डॉ. व्यास आज स्काडा बिजनेस सेंटर हॉल में 'वाणी' और 'आभा' स्वैच्छिक संगठनों द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे।

प्रभात खबर
अखबार नहीं आंदोलन

खूबसूरत वायदे के समान है राष्ट्रीय नीति

स्काडा बिजनेस सेंटर में 'स्वैच्छिक क्षेत्रक राष्ट्रीय नीति, 2007' पर एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न

पटना : स्वैच्छिक क्षेत्रक राष्ट्रीय नीति, 2007 पर हुई संगोष्ठी में उपवन के कार्यकारी निदेशक सीएस व्यास ने कहा कि यह निश्चित रूप से सरकार की अच्छी पहल है, लेकिन इसमें अच्छाइयों के साथ-साथ कुछ कमियां अभी भी शेष हैं, जिसे राज्य में बननेवाली राज्य नीति में सुधार कर दूर किया जा सकता है. उन्होंने राष्ट्रीय नीति को खूबसूरत वायदा कहते हुए कहा कि इसकी नीतियों की घोषणा हुए लगभग सात महीने बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी तरह का क्रियान्वयन नहीं हो सका है.स्काडा बिजनेस सेंटर में शनिवार को वाणी व आभा, नयी दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया. उन्होंने कहा कि ब्लैक लिस्टेड सिर्फ एनजीओ ही नहीं, बल्कि उक्त संस्था को राशि मुहैया करानेवाले अधिकारी को भी दंडित किया जाना चाहिए. आद्री के निदेशक सीपी घोष ने कहा कि मनुष्य के लिए सारे काम व्यक्तिगत नहीं होते, बल्कि उसमें सामाजिकता भी होती है. इसी के तहत लोक जनोपयोगी कार्य करते हैं. किसी भी मनुष्य या संगठन के लिए यदि सामाजिक सरोकार गहरे हों, तभी समाज में उसकी खास पहचान बनती है. संगोष्ठी को अवनेश कुमार, गणेश प्रसाद, रमेश कुमार तथा वाणी के राज्य संयोजक प्रणव कुमार ने भी संबोधित किया.

दैनिक जागरण

'सामाजिक समस्याओं से निपटने के लिए सरकार व संगठनों में तालमेल जरूरी'

पटना, हमारे प्रतिनिधि : सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए सरकार एवं स्वयंसेवी संगठनों में तालमेल जरूरी है। ये बातें शनिवार को वालेन्ट्री एक्शन नेटवर्क फोरम के तत्वावधान में स्काडा बिजनेस सेंटर में आयोजित सेमिनार में विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने कहीं। सभा के अध्यक्ष एवं सामाजिक संगठन उपवन के कार्यकारी निदेशक व्यास जी ने कहा कि ब्लैक लिस्टेड संगठनों को दण्डित किया गया लेकिन उन्हें धन देने वाले अधिकारी अभी माल मार हैं। कार्यक्रम का आयोजन सामाजिक संगठन वाणी एवं आभा के संयुक्त तत्वावधान में स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय नीति चर्चा करने के लिए किया गया।

इस अवसर पर अदिति के गणेश जी, प्रिया के विश्व रंजन, ओम प्रकाश, अमरेन्द्र कुमार सहित कई लोगों ने भाग लिया।